

FA-832(TAMP)  
13/2/14



ST - 14-02-14

V-32  
13/2/14

सार्वजनिक भवन का नाम : भारतीय टारिफ़ बोर्ड  
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

चतुर्थ तला, भारतीय भवन, मुंगांव, पालघाड़ी रोड, माझगांव, मुंबई - 400 010.

4th Floor, Bhandar Bhawan, Muzawar Pakhad Road, Mazgaon, Mumbai - 400 010.  
Tel.: 2379 2000, 2379 2000 Fax: 022-2375 7879, E-mail: tariff@tariffauthority.gov.in, Web: http://www.tariffauthority.gov.in

No.TAMP/6/2010-KOPT  
11 February 2014

To

The Chairman,  
Kolkata Port Trust,  
15, Strand Road,  
Kolkata-700001.

FAccAO/C

A/c to ADC and all  
P.I. intm officers & P.D.S. Branch  
Senior officers  
13/2/14

Subject: Extension of the validity of the existing Scale of Rates of  
Kolkata Port Trust.

Sir,

Please refer to your letter no. Fin/603/B dated 03 January 2014 on  
the subject cited above.

2. This Authority had passed an Order on 10 January 2014 extending  
the validity of the existing Scale of Rates till 31 March 2014 or till the effective date  
of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier. This Order  
has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 10  
February 2014 vide Gazette No.46. A copy of each of the Notification and Order  
(both in Hindi and English) thereof is enclosed herewith for your information and  
appropriate action.

3. The Notification and Order can also be downloaded from our  
website <http://tariffauthority.gov.in>.

4. Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

(Jyothi Venkatachalam)  
Deputy Director

Encl.: As above.

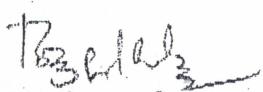
(To be published in Part - III Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary)  
**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

No. TAMP/6/2010-KOPT

Mumbai, 4 February 2014

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by Section 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at Kolkata Port Trust as in the Order appended hereto.

  
**(T.S. Balasubramanian)**  
Member (Finance),

**Tariff Authority for Major Ports**  
**Case No.TAMP/8/2010-KOPT**

The Kolkata Port Trust

Applicant

**QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)  
(ii). Shri. Chandra Bhushan Singh, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on this 10<sup>th</sup> day of January 2014)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Kolkata Port Trust (KOPT).

2. The existing Scale of Rates of KOPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/8/2010-KOPT dated 29 November 2010 which was notified in the Gazette of India on 15 February 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March 2013. This Authority has extended the validity of SOR of KOPT twice. This Authority has last extended the validity of the existing SOR of KOPT till 31 December 2013 vide its Order dated 29 October 2013.

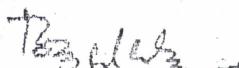
3. The proposal filed by the KOPT vide its letter dated 30 January 2013 was taken on consultation with the concerned users/ user association. The additional information / clarification sought from the KOPT vide our letter dated 22 May 2013 has been furnished by the port vide its letter dated 14 August 2013 and 20 August 2013. The proposal of KOPT and replies furnished by the port are being examined and it will take time for the case to mature for consideration of this Authority.

4. In the meantime, the KOPT vide its letter dated 3 January 2014 has stated that as the joint hearing is over and as the requisite clarifications have been furnished, that Authority may extend the existing SOR till issuance of the final order.

5. In the meantime, the Government in Ministry of Shipping (MOS) has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 till 31 March 2014 or until further orders. As advised by the MOS, this Authority has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 vide its Order No. TAMP/21/2009-WS dated 20 December 2013 which is notified in the Gazette of India on 26 December 2013 vide G. No. 340.

6. The validity of the existing SOR expired on 31 December 2013. Recognizing that it will take time for finalization of the case and also recognizing that the validity of the Tariff Guidelines, 2005 is extended till 31 March 2014, this Authority extends the validity of the existing SOR of the KOPT including 4% surcharge for the reasons recorded in Order dated 9 May 2013 till 31 March 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

7. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return accrues to the KOPT post 1 April 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be fully adjusted in the tariff to be fixed for the next cycle.

  
**(T.S. Balasubramanian)**  
Member (Finance)

(भारत का शज्जल के बारे—II) खंड 4 में प्रकल्पानाम्

महाप्रतिवेदन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. लीएप्री/६/२०१०-कोओपीटी

मुम्बई, ५ फरवरी 2014

अधिसंघना

महाप्रतिवेदन न्यायस अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाप्रतिवेदन प्रशुल्क प्राधिकरण एवं द्वारा संलग्न आदेशानुसार, योतकाता पत्रन न्यायस की गोप्यता दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

को।

(टी.एस. बालासुब्रहमण्य)

सदस्य (विच)

महाप्रतिनिधि प्रशुल्क प्राधिकरण  
मालारा बा. टीएमपी/८/२०१०-केओपीटी

आवेदक

फोलकारा एस्टेट व्हाल्स

ठारेस्ट

- (i). श्री टी.एस. मालारुद्धमप्पन, आदेश (वित्त)  
(ii). श्री चन्द्र भगवन सिंह, सदस्य (अधिकारी)

आदेश

(जनवरी २०१४ के १०वें दिन पारित)

यह मालारा कोलकाता महानगरपालिका (केओपीटी) के नीजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से सम्बंधित है।

१. केओपीटी का नीजूदा दरमान इस प्राधिकरण द्वारा जिल्ही बार आदेश बा. टीएमपी/८/२०१०-केओपीटी दिनांक २० अक्टूबर २०१०, दिसंबर २०१३ द्वारा दो शासकीय वैधिकीयता किया गया था, दारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरकान की वैधता ३१ मार्च २०१३ तक विस्तारित करता है। यह प्राधिकरण केओपीटी के दरमान की वैधता दो बार विस्तारित कर दिया है। इस प्राधिकरण ने केओपीटी के नीजूदा दरमान की कैलाना विचली बार अपने आदेश दिनांक २० अक्टूबर २०१३ द्वारा ३१ दिसंबर २०१३ तक विस्तारित की थी।

२. केओपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक ३० अक्टूबर २०१३ द्वारा पारित किए गए प्रत्यावरण पर संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता असोशिएशन के साथ विकास-विनियोग किया गया है। इनके पत्र दिनांक २२ मई २०१३ द्वारा केओपीटी से नांगी गई अतिरिक्त रुगमा/रुद्धीकरण घटना क्षेत्र अपने पत्रों दिनांक १४ अगस्त २०१३ और २० अगस्त २०१३ द्वारा भेजा गया है। केओपीटी के प्रत्यावरण और पत्तन द्वारा प्रेषित जवाबों की जांच भी जा रही है और इस प्राधिकरण द्वारा विचार कर अंतिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा।

३. इसी बीच, केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक ३ जानवरी २०१४ द्वारा बताया है कि चूंकि संयुक्त सुनवाई खल्म हो चुकी है और यथा अपेक्षित सार्वजनिकरण भेजे जा चुके हैं, इसलिए यह प्राधिकरण मौजूदा दरमान को अंतिम आदेश जारी किए जाने तक विस्तारित करे।

४. इसी बीच, गोत परिवहन मंज़ालग (एमओएस) में सरकार ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, २००५ की वैधता ३१ मार्च २०१४ तक अधिवा अगले आदेश तक विस्तारित की है। एमओएस द्वारा दी गई जलाड अनुसार, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश बा. टीएमपी/२१/२००९-उत्क्षयूक्ष दिनांक २० दिसंबर २०१३, जिसे जी.रा. ३४० द्वारा २० दिसंबर २०१३ को भारत के राजपत्र में अधिरूपित किया गया है, द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश, २००५ की वैधता को विस्तारित किया है।

५. नीजूदा दरमान की वैधता ३१ दिसंबर २०१३ को समाप्त हो चुकी है। यह स्वीकार करते हुए कि मामले को अंतिम रूप देने में समय लगेगा और यह भी स्वीकार करते हुए कि प्रशुल्क दिशानिर्देश, २००५ की वैधता ३१ मार्च २०१४ तक विस्तारित की गई है, यह प्राधिकरण आदेश दिनांक ९ मई २०१३ में दर्ज किए गए कारणों से ५ प्रतिशत अधिभार सहित केओपीटी के नीजूदा दरमान की वैधता ३१ मार्च २०१४ तक अधिवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावीता तोड़ी दी जा सकती है।

६. यदि स्वीकार्य सामग्री और स्वीकार्य प्रतिलिपि से अधिक कार्ड अतिरिक्त अविलम्ब १ अप्रैल २०१३ के बाद प्रोक्षण होता है तो इसके कार्यनिष्ठादान की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष अगले चक्र के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः शामायोजित किया जाएगा।

लाला

(टी.एस. मालारुद्धमप्पन)  
सदस्य (वित्त)